हिन्दी साप्ताहिक

बतकही

RNI No. UPHIN/2021/82967

वर्ष 3 अंक 49+50 फतेहपुर, सोमवार 22 जुलाई 2024 पृष्ठ 4 मूल्य 1 रूपया

बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के एक राज्य में कृषि कार्य में अत्यधिक फर्टिलाइजर के उपयोग का हश्र यह हुआ कि आज वहां से कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति से कृषि उत्पादन जरूर बढ़ा, मगर ये अधूरा सच है। आज फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण एक धीमा जहर हमारी धमनियों में घुस रहा है। ये दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि पशु–पक्षी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। देश में कई इलाके ऐसे भी थे, जहां प्राकृतिक ढंग से भी कृषि उत्पादन अधिक था। हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में जल्द ही एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित किया जाएगा। हमें खेती को लेकर पिछले सौ–डेढ़ सौ वर्ष में जो पढ़ाया गया है, उसमें और पुराने समय के विज्ञान में कितना अंतर है। हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। हरित क्रांति के बाद जब खेती में फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ तो कुछ समय तक उत्पादन तो बढ़ा, मगर आज एक स्लो प्वाइजन के रूप में वह हमारी धमनियों में घुसता जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि फर्टिलाइजर का दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों में ही नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि पशु–पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अमरोहा में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल में 12 से 14 गाय अचानक मर गईं, हमने वहां विशेषज्ञ भेजे तो ये पता लगा कि चारे में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर मिला था, जिसके कारण उनकी मौत हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें समझना होगा कि जब गाय अत्यधिक फर्टिलाइजर को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तो मनुष्य की स्थिति क्या होगी। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए धन की मांग करते हैं, इसमें सर्वाधिक मामले कैंसर के होते हैं। आज से कुछ साल पहले इतनी भयावह स्थिति नहीं थी। आज गांव–गांव में युवाओं में कोई किडनी, कोई हार्ट तो कोई कैंसर से पीड़ित हो गया है। इसका कारण है कि हमारा खानपान कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। इससे बचाव का नया मंत्र पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती का दिया है।

दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा केंद्र सरकार दिल्ली के विकास पर खर्च नहीं करती

नयी दिल्ली । दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली वालों के दिए टैक्स के पैसे से दिल्ली को कुछ नहीं मिलता। केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए दिए जा रहे पैसों को भी रोक लिया है। आतिशी के मुताबिक, 23 जुलाई को केंद्र सरकार अपना बजट ला रही है। ये बजट किसके पैसे से तैयार होता है। ये जनता और राज्य सरकारों के पैसे से बनाया जाता है जिसका उनको ही लाभ नहीं मिल रहा है। दिल्ली वालों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली सरकार को आता है। जिसमें जीएसटी, वैट समेत अन्य कंपोनेंट होते हैं। आतिशी ने कहा, पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार को 35 हजार करोड़ का टैक्स मिला था, जो दिल्ली के विकास के लिए खर्च होना है। जिसमें दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे बिजली, मोहल्ला क्लीनिक बनाने में, बच्चों के लिए स्कूल बनवाने में, पानी के लिए पाइप लाइन पहुंचाने में, दिल्ली में आ रही मोहल्ला बसों पर, नए फ्लाईओवर पर और अन्य सुविधाओं पर दिल्ली सरकार खर्च करती है। उन्होंने कहा, दिल्ली वालों ने इनकम टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा जीएसटी का भी एक हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है जिसके मुताबिक 25 हजार करोड़ रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को गया है। कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों ने 2.32 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को दिया है। आतिशी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब दिल्ली वाले इतना ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं तो दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। इसका जवाब है जीरो। आतिशी ने बताया कि दिल्ली वालों के लिए एक पैसा भी इस टैक्स से केंद्र सरकार ने खर्च नहीं किया है। अगर बड़े टैक्स पे करने वालों की बात करें तो मुंबई से भी 5 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। महाराष्ट्र जब इतना टैक्स देता है तो उसे 54 हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बैंगलोर की बात करें तो यह भी दिल्ली जितना ही 2 लाख करोड रुपए टैक्स केंद्र को देता है, जिसके एवज में कर्नाटक को 33 हजार करोड़ दिया जाता है। लेकिन दिल्ली वालों को 1 रुपए भी नहीं मिलता। आतिशी ने कहा है कि इस बार दिल्ली वालों की मांग है कि उन्हें उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। अंग्रेजों के समय में जो भारत के साथ होता था, वही अब दिल्ली वालों के साथ किया जा रहा है। इस बार केंद्र सरकार से दिल्ली वालों को 10 हजार करोड़ रुपए मिलना चाहिए ताकि विकास कार्यों में और तेजी आए। यह भारत सरकार के पूरे बजट का 0.25 प्रतिशत है। हमने कहा है कि जो दिल्ली इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन देती है उसका यह मात्र 5 प्रतिशत है।

एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की विशेषता बताएंगे : शिवराज

लखनऊ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में शुक्रवार को प्राकृतिक खेती पर आधारित श्भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धतिश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कम से कम एक करोड़ किसानों के बीच जाकर उन्हें प्राकृतिक खेती की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि हम कम से कम एक करोड़ किसानों तक जाएंगे और प्राकृतिक खेती की विशेषता से अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनमें से 18 लाख किसान ऐसे निकलें, जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें। अगर आपके पास 5 एकड़ खेत है तो एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करें। अगर आपके पास दो एकड़ खेत है तो आधे एकड़ में करें, बाकी में आपको जो करना है, करते रहें। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय एक और प्रयोगशाला बनेगी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बनाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र को हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेत भी प्रयोगशाला होंगें। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पहले और दूसरे साल तक उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन, तीसरे साल में ज्यादा होगा। इसलिए, तीन साल तक हम किसानों के खाते में कुछ पैसे डालेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर पर भी तो सब्सिडी दे ही रहे हैं, तो प्रोत्साहन के लिए ये भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती से किसानों को जब लाभ होगा तो वह खुद खेती करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में अगर एक किसान सफल हो गया तो वह इस खेती को और बढ़ाएगा और दूसरे किसान भी प्रभावित होंगे। धीरे–धीरे देश में प्राकृतिक खेती होने लगेगी। आज–कल इतनी जागरूकता हो गई है कि लोगों को जब पता चलेगा कि प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ है। तो, लोग उसे डेढ़ गुना दाम पर खरीद लेंगे। मैं हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए आप सब लोग जो तय करेंगे, उसे हम फॉलो करेंगे। कई बार मंत्री बनकर यह गुमान हो जाता है कि अपन ही सब कुछ हैं। लेकिन, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति, हर विषय का जानकर नहीं हो सकता, यहां विशेषज्ञ बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन और सलाह लेंगे।

राज्यपाल ने प्रोफेसर डॉक्टर विनीता लाल की लैंगिक समाजशास्त्र शीर्षक की पुस्तक का किया विमोचन

लखनऊ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ की समाजशास्त्र विभाग की प्रभारी प्रोफ़ेसर(डॉ) विनीता लाल की ष्लैंगिक समाजशास्त्रष शीर्षक की पुस्तक का विमोचन आदरणीय राज्यपाल उ०प्र० महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के कर कमलों के द्वारा राजभवन में किया गया। यह पुस्तक जिज्ञासु परास्नातक छात्र–छात्राओं एवं शोधार्थियों हेतु लाभकारी विषय वस्तु की अमूल्य स्रोत है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में निर्धारित स्नातक एवं परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को पूरी तरह समाहित करती है। उक्त पुस्तक विभिन्न सामाजिक विषयों के सुधी और विचारवान पाठकों हेतु अत्यंत लाभकारी है।

इस गौरवपूर्ण अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय ,लखनऊ पुस्तकालय प्रभारी डॉक्टर ममता लाल एवं अप्लाइड इकोनॉमिक्स की शोध छात्रा कुमारी मानसी भी उपस्थित थी।

सम्पादकीय

सेहत की कैंटीन

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि भारत धीरे–धीरे मधुमेह, ह्रदय रोग व मोटापे की राजधानी बनता जा रहा है। देश के हर चार में से एक व्यक्ति मोटापे व प्री–डायबिटिक स्थिति में पहुंच गया है। संकट इसलिए बड़ा है कि किशोर व युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। रात दिन मोबाइल–लेपटॉप में लगे रहने और शारीरिक श्रम से दूर पीढ़ी के लिए फास्ट फूड खासा घातक साबित हो रहा है। यही वजह है कि कई सर्वेक्षणों के निष्कर्ष व विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद देश के विश्वविद्यालयों का नियमन करने वाली राष्ट्रीय संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों को निर्देश दिये हैं कि कॉलेज की कैंटीन में पिज्जा, बर्गर और समोसे जैसे जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाई जाए।। दरअसल, छात्रों में बढ़ते मोटापे और मोटापे से जनित अन्य रोगों की समस्या के मद्देनजर यूजीसी ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तुरंत रोक लगायी जाए। निस्संदेह, नई पीढ़ी में जंक फूड को लेकर खासा क्रेज है, लेकिन युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाल के दिनों में युवाओं में मधुमेह, मोटापे व ह्रदय संबंधी विकार के मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ माह पूर्व आयी आईसीएमआर की रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी कि देश में तेजी से बढ़ रहे अल्ट्रा–प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में वसा की अधिक मात्रा पायी जाती है। जो मोटापा बढ़ने का बड़ा कारण है। जो कालांतर ह्रदयाघात,डायबिटीज आदि गैर संक्रामक बीमारियों की वजह बनता है। आईसीएमआर ने अच्छे स्वास्थ्य को मानव के मौलिक विशेषाधिकार की संज्ञा दी है। दूसरी ओर मानव पोषण, महामारी विज्ञान, चिकित्सा शिक्षा, बाल रोग व सामुदायिक उपचार आदि के स्वतंत्र विशेषज्ञों के राष्ट्रीय थिंक टैंक एनएपीआई ने भी इसी प्रकार की चिंताएं जतायी हैं। एनएपीआई ने भी शैक्षणिक संस्थानों में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर तुरंत रोक लगाने की सलाह दी है। साथ ही कैंटीन में स्वस्थ खाद्य पदार्थों के विकल्प बढ़ाने पर जोर दिया है।बहरहाल, अब शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों व शिक्षकों का दायित्व है कि कालेजों की कैंटीनों में स्वस्थ खाद्य पदार्थों के विकल्प उपलब्ध ा करायें। साथ ही छात्रों को इस दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित करें। निस्संदेह, केवल यूजीसी के निर्देशों से हालात बदलने वाले नहीं हैं। दरअसल, यूजीसी ने इस बाबत पहली बार दिशा–निर्देश नहीं दिये हैं। इससे पहले दस नवंबर 2016 तथा इक्कीस अगस्त 2018 को भी इसी तरह के परामर्श जारी किये गए थे। विडंबना यह है कि युवा पीढ़ी पाश्चात्य खानपान शैली का अंधानुकरण कर रही है। किसी देश का खानपान उस देश की जलवायु तथा रोगों की आनुवंशिकता के आधार पर तय होता है। युवा पीढ़ी मौसमी फल, सब्जियों तथा परंपरागत खाद्य पदार्थों से परहेज कर रही है। सदियों से हमारे खानपान में उन तमाम खाद्य पदार्थों से परहेज किया गया, जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं और त्रिदोष को बढ़ावा देने वाले हैं। सही मायने में हमारे खानपान में एसिड बढ़ाने वाले पदार्थों का बोलबाला है। जबकि हमें क्षारीय प्रवृत्ति वाले खाद्य पदार्थों का सेवन भी संतुलन के लिये करना चाहिए। दरअसल, समय के साथ देश में संपन्नता आई है और समृद्ध खानपान की शैली विकसित हुई है, लेकिन विडंबना यह है कि हमारी जीवन शैली में श्रम की प्रधानता घटी है। श्रमशील व गतिशील व्यक्ति को सब कुछ हजम हो जाता है, लेकिन निष्क्रिय जीवन शैली मोटापे, मधुमेह व ह्रदय रोगों को बढ़ावा देती है। चिंता की बात यह है कि जो रोग पहले व्यक्ति को पचास साल के बाद होते थे, वे अब किशोरों व युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। हाल ही में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने खुलासा किया था कि कैसे भारत में पचास फीसदी लोग सप्ताह में जरूरी व्यायाम व सैर तक नहीं करते। निश्चित रूप से यह एक राष्ट्रीय संकट का प्रश्न है। जिसके चलते आने वाले दिनों में देश गैर संक्रामक रोगों की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी छात्रों को स्वस्थ खानपान के प्रति जागरूक करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय में मनी बिल को चुनौती

सत्तारूढ़ भाजपा की कमजोरी और बढ़ी

के रवींद्रन

अगर आधार एक पैसे का मामला है, तो किसी भी चीज का मतलब कुछ भी हो सकता है। यह उन प्रमुख दुविधाओं में से एक होगी, जिस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ विचार करेगी, जब वह विवादास्पद विधेयकों को आगे बढ़ाने में विधायी बाधाओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार द्वारा मनी बिल वाले मार्ग के अनुचित इस्तेमाल के खिलाफ याचिकाओं पर विचार–विमर्श शुरू करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस सप्ताह फैसला किया कि समय आ गया है कि विद्वान न्यायाधीश काम पर लग जाएं, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में जब से बेंच की घोषणा की गयी थी, तब से बेंच लगभग निष्क्रिय रही है। यह मुद्दा भारतीय संविधान की धारा110 की व्याख्या और अनुप्रयोग पर केंद्रित है, जो परिभाषित करता है कि मनी बिल क्या होता है।

धन विधेयक, सामान्य विधेयकों के विपरीत, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना पेश और पारित किये जा सकते हैं, जिससे विपक्ष के प्रभुत्व वाले उच्च सदन की जांच और संभावित अवरोध को प्रभावी ढंग से दरकिनार किया जा सकता है। सरकार ने आधार कानून को धन विधेयक के दायरे में लाने के लिए कमजोर वर्गों को प्रभावी सब्सिडी प्रदान करने के साधन के रूप में आधार की एक दूरगामी परिभाषा प्रदान की थी। लेकिन इसने व्यापक रूप ने लोगों को चौंका दिया था।

विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों सहित आलोचकों का तर्क है कि सरकार संसदीय निगरानी से बचने और जल्दबाजी में कानून बनाने पर रोक लगाने के लिए राज्यसभा की भूमिका को कमजोर करने के उद्देश्य से धन विधेयक प्रावधान का दुरुपयोग कर रही है। उनका तर्क है कि धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत कई विधेयक संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और राज्यसभा में विपक्ष को दरकिनार करने के लिए उन्हें गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। उनका तर्क है कि यह प्रथा लोकतांत्रिक विचार–विमर्श और विधायी जांच के सिद्धांतों को नष्ट करती है जो मजबूत और अच्छी शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। राज्यसभा में विधायी गतिरोध का सामना कर रही मोदी सरकार ने प्रमुख सुधारों और ऐतिहासिक कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से इस मार्ग की ओर रुख किया है। जहां तक भाजपा और मोदी सरकार का सवाल है, स्थिति एक कीचड़युक्त अतीत से और अधिक कीचड़ वाले भविष्य की ओर इशारा करती है। राज्यसभा में भाजपा की ताकत घटकर 86 रह गयी है, जिससे एनडीए की विधायी क्षमता प्रभावित हुई है। अन्य सहयोगियों को शामिल करने पर, ताकत बढ़कर केवल 101 रह जाती है। इसका उच्च सदन में विवादास्पद विधेयकों के पारित होने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, सरकार को लगातार राज्य चुनावों के बाद बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां विपक्षी दलों ने अपनी सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़त हासिल की है। कम ताकत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बढ़ती विपक्षी एकता के साथ, सरकार को विवादास्पद तरीकों का सहारा लिए बिना विधायी जनादेश हासिल करने में एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यकारी आदेशों और अध्यादेशों के माध्यम से शासन की प्रभावकारिता और वैधता पर भी इस संदर्भ में सवाल उठाये गये हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन और संसदीय जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ गयी हैं। विभिन्न हितधारकों द्वारा दायर याचिकाओं में धन विधेयक लेबल के तहत पारित विधेयकों की वैधता पर सवाल उठाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस तरह का वर्गीकरण मनमाना था और राज्यसभा में बहस और संशोधन से बचने के लिए बनाया गया था।

ये याचिकाएँ विशिष्ट विधायी उदाहरणों को उजागर करती हैं, जहां कराधान और वित्त से संबंधित विवादास्पद विधेयकों को वित्तीय मामलों से परे उनके व्यापक निहितार्थों के बावजूद धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी चुनौती केवल संवैधानिक प्रावधानों की तकनीकी व्याख्या के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए व्यापक निहितार्थों के बारे में भी है। यह कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों के संतुलन और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाये रखने में न्यायिक निगरानी की भूमिका के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है। इन चुनौतियों के जवाब में, सरकार ने विधायी गतिरोध को दूर करने और महत्वपूर्ण सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में धन विधेयक मार्ग के अपने उपयोग का बचाव किया है। यह तर्क देता है कि विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना कानूनी सलाह और संसदीय परम्परा के अनुसार किया गया था, जो आर्थिक और राजकोषीय नीति के मामलों में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल देता है।

इन याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि इसमें भविष्य की विधायी प्रथाओं और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए एक मिसाल कायम करने की क्षमता है। तात्कालिक कानूनी निहितार्थों से परे, इस मामले का भारत के लोकतांत्रिक शासन, न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन पर व्यापक प्रभाव है।

मेडिकल-कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने की आत्महत्या

उरई/जलौन(संवाददाता)। जालौन में मेडिकल कॉलेज की छत से कूदकर एक मरीज ने आत्महत्या कर ली। वह तीन दिन पहले ही घर की सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जिन्होंने मरीज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना उरई कोतवाली के कालपी रोड स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की है। बताया गया कि 17 जुलाई को जालौन नगर के रहने वाले अजब सिंह (50) पुत्र शंकर सिंह सीढ़ियों से फिसलकर घायल हो गया था। जिसे कुछ लोगों ने राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने इमरजेंसी के बाद 17 जुलाई को ही उसे मरीजों वाले वार्ड नम्बर 7 में शिफ्ट कर दिया था। भर्ती कराने के बाद उससे मिलने के लिए कोई भी परिजन मेडिकल कालेज नहीं पहुंचा था। डॉक्टर उसका इलाज भी समय से कर रहे थे। शुक्रवार की दोपहर को बारिश हो रही थी। इसी दौरान अजब सिंह मेडिकल कॉलेज की छत पर चढ़ गया, जिसने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही वहां के कर्मचारियों ने उसे कूदते देखा तो तुरंत मेडिकल प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने तुरंत उसे इलाज के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि मरीज के कूदने की सूचना पर उपनिरीक्षक को भेजा गया था। अभी तक उसके परिजनों का पता नहीं लग सका है।

योगी सरकार में पत्रकारों का विशेष सम्मान : धर्मपाल

सूचना विभाग के विज्ञापन वितरण में भेदभाव को दूर किया जायेगा

पीलीभीत (संवाददाता)। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि योगी सरकार में पत्रकारों का सम्मान बढ़ा है। सरकार निरंतर पत्रकारों के हित में काम कर रही है। श्री धर्मपाल सिंह पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जिला एवं तहसील इकाईयों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

इस दौरान उनके समक्ष सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा विज्ञापन वितरण में भेदभाव का मुद्दा भी उठा। जिस पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार यूपी में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। विज्ञापन वितरण के संबंध में सूचना निदेशक को निर्देश दिया जायेगा कि इस मामले में कोई भेदभाव मत करें। जिला सूचना कार्यालय की बिल्डिंग को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार पहली प्राथमिकता विकास की है। पीलीभीत जिले में सूचना विभाग की अपनी जमीन है लेकिन किसी कारण बस बजट आवंटित नहीं हो सका है। सरकार शासन से इस मामले में खास पैरवी की जायेगी और आश्वस्त करता हु कि इसमें प्रभावी पैरवी की जायेगी। विशिष्ट अतिथि बरेली मेयर डा. उमेश गौतम ने कार्यक्रम में समा बांधते हुए पत्रकारों की बात करते हुए किसी भी विषम परिस्थितियों में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजेश त्रिवेदी ने समाचार पत्रों की आर्थिक समस्याओं को बेबाकी से उठाया, जबकि प्रदेश महामंत्री रमेश शंकर पांडेय ने उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञापन नीति की विसंगतियों पर गंभीर चर्चा के साथ पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि मेयर बरेली डा. उमेश गौतम, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेश त्रिवेदी, महामंत्री रमेश शंकर पांडेय, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह एवं मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह ने पत्रकारों को उनके पद एवं कर्तव्य की शपथ दिलाई। शहर के आकेजन बैंकट लॉन में जिला अध्यक्ष हरिपाल सिंह के नेतृत्व में पीलीभीत की गजरौला इकाई, पूरनपुर इकाई, बिलसंडा इकाई, बरखेड़ा इकाई, बीसलपुर इकाई, अमरिया इकाई समेत जिले की इकाई के पदाधिकारियों समेत कार्यकारिणी सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में कुमार विनय, दीपक शर्मा, अमित नारायण शर्मा, राशिद अली, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी विपिन कुमार, प्रदेश संगठन मंत्री सुधीर कुमार दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार रविंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह, चंद्रदेव अवस्थी, पीलीभीत जिलाध्यक्ष हरिपाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जदेव सिंह, उपाध्यक्ष करन सिंह चौहान, विक्रांत शर्मा, महेश कौशल, आशुतोष मिश्रा, सुरेश जायसवाल, पूरनपुर अध्यक्ष राम करन शर्मा, सर्वेश शर्मा, मो. आरिफ समेत सात इकाई के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

तेलंगानाः एक लाख रुपये की कर्ज माफी में अंडोल सबसे आगे

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई एक लाख रुपये की कृषि ऋण माफी में अंडोल निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना में पहले स्थान पर है, जहां 107 करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि माफ की गई है। अंडोल के बाद हुस्नाबाद और कलवाकुर्ती ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। गुरुवार को, राज्य सरकार ने राज्य के 110 निर्वाचन क्षेत्रों (नौ शहर निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर जहां कोई किसान ऋण नहीं है) में 10,84,050 किसान परिवारों के 11,50,193 किसानों के ऋण खातों में 6,098.93 करोड़ रुपये जमा करते हुए एक लाख रुपये तक के ऋण माफ कर दिए। इस पहल से वे सभी परिवार कर्ज मुक्त हो गए हैं। अंडोल निर्वाचन क्षेत्र में, 19,186 किसान परिवारों के 20,216 किसानों के 107.83 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, हुस्नाबाद निर्वाचन क्षेत्र में, 18,101 किसान परिवारों के 18,907 किसानों के 106.74 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए।

बिहारः जीतन सहनी हत्या मामले में अब भी अनसुलझे हैं कई सवाल

दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी कई आरोपी फरार बताये जा रहे हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं, जिसके जवाब पुलिस अब तक नहीं खोज पाई है। जीतन सहनी की अज्ञात अपराधियों ने सोमवार देर रात निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। मंगलवार सुबह उनका शव दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित उनके आवास से बरामद किया गया था। अगले दिन बुधवार को ही पुलिस ने काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया था।

पुलिस अब तक हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर पाने में सफल नहीं हो सकी है। पास के एक जलाशय के पानी को निकालकर भी हथियार की खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर, वीआईपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी बिहार के पुलिस महानिदेशक से मिला, जहां एक आवेदन पत्र देकर अनुसंधान की दिशा भटकने की आशंका जताई गई।मृतक के भतीजे पवन सहनी द्वारा लिखे आवेदन पत्र में कहा गया है कि इस हत्या मामले में पुलिस द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान से अनुसंधान की दिशा भटकने की आशंका है। आवेदन में कई सवाल भी उठाए गए हैं। आवेदन में कहा गया है कि अपराध में उपयोग किये गए हथियार की भी बरामदगी नहीं हो पाई है। आवेदन में कहा गया है कि अनुसंधान अब तक प्रारंभिक अवस्था में है। मीडिया में 10 जुलाई की रात का सीसीटीवी फुटेज चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10–15 लोग घटनास्थल के समीप लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। इधर, पुलिस मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी को रिमांड पर देने का न्यायालय से आग्रह करेगी, जिससे और पूछताछ की जा सके। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पुलिस अब तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही है। उस क्रम में मोबाइल नंबर का भी विश्लेषण किया जा रहा है। घटनास्थल से जो कागज, बाइक और अन्य सामान बरामद हुए हैं, उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आरोपी द्वारा बताए गए अन्य आरोपियों का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस सावधानी बरत रही है कि कोई निर्दोष न फंसे। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है।

ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी द्वारा एफआईआर

नयी दिल्ली। दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने नाम, माता–पिता का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाई। यही कारण है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा–2022 की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के कदाचार की विस्तृत और गहन जांच की है। आयोग के मुताबिक इस जांच से यह पता चला है कि उसने नाम, पिता और माता का नाम, तस्वीर हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। यूपीएससी का कहना है कि इसलिए, यूपीएससी ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसके अंतर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराकर आपराधिक अभियोजन शामिल है। इसके अलावा सिविल सेवा में उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। सेवा परीक्षा–2022ध सिविल सेवा परीक्षा–2022 के नियमों के अनुसार उसे भविष्य की परीक्षाओंध्चयनों से प्रतिबंधित किया गया है। यूपीएससी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी कर्तव्यों का सख्ती से पालन करता है। यूपीएससी के मुताबिक वह बिना किसी समझौते के उचित उच्चतम मानदंडों के साथ सभी परीक्षाओं सहित अपनी सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

पश्चिम बंगाल में महिला के काटे गए बाल

सुवेंदु ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को दयनीय बताते हुए एक वायरल वीडियो पोस्ट किया है। इस दावे के साथ कि महिला के बाल काट रहे लोग टीएमसी से जुड़े हैं। भाजपा नेता ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा, ये शर्मनाक है। इस बार ये हावड़ा का दोमजूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोमजूर कोई सुदूर इलाका नहीं है। यह हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिग्गज भाजपा नेता ने प्रदेश के विभिन्न जिलों–इलाकों में महिला उत्पीड़न का जिक्र भी किया है। कहा, कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादहा से दोमजूर तक, यह पीड़ा जारी है।सजा के तौर पर कल एक महिला के बाल कैंची से बेरहमी से काटे गए!सुवेंदु ने बाल काटने वालों के नाम भी बताए हैं। दावा किया, इस वीभत्स कृत्य को अंजाम देने वाले दरिंदे – ईशा लश्कर, अबुल हुसैन लश्कर, सायम लश्कर, मकबूल अली, इसराइल लश्कर, अरबाज लश्कर और महेबुल्लाह मिद्दे, टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पोस्ट के अंत में उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। इसे दमघोंटू बताते हुए तंज भी कसा है। लिखा है, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी एयर टाइट है कि पूरे राज्य में कंगारू कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं और तुरंत न्याय मिल रहा है, खासकर महिलाओं को! दरअसल, अधिकारी ने कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादहा से दोमजूर का जिक्र इसलिए किया।

डिप्टी सीएम से मिलकर सीएचसी अधीक्षक की हुई शिकायत

खखरेरू फतेहपुर। सूबे के योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का अचानक फतेहपुर जिला अस्पताल का दौरा हुआ तभी खखरेरू निवासी जीतू शुक्ला ने डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर खखरेरू सीएचसी अधीक्षक की स्वास्थ्य मंत्री से की शिकायत डिप्टी सीएम ने सीएमओ राजीव नयन गिरी को जांचकर कर कार्यवाही करने के निर्देश दिया साथ ही मंत्री जी ने आश्वस्त किया की आपको न्याय जरुर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बावजूद कि कोई भी सरकारी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी इसके बावजूद भी सीएचसी अधीक्षक पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप लग रहा है इसकी घहनता से जांच होना चाहिए वार्ड नं 8 अहिल्या बाई नगर के जीतू शुक्ला ने सीएमओ को दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया है की सीएचसी इन्चार्ज राजू राव जो लेवल वन के अधिकारी हैं उनके द्वारा स्थानीय नेता के दबाव में मेरा सिटी स्कैन नहीं लिखा गया था साथ ही पिछले दिनों संदीप पाल जो लक्ष्मीबाई नगर का रहने वाला है जिसके सर में गंभीर चोटें आई थीं उसका भी सिटी स्कैन नहीं लिखा गया था जिसके सर की हड्डी टूटी थी सीएचसी इन्चार्ज राजू राव द्वारा मेडिकल में लापरवाही स्थानीय नेता के दबाव में की जाती है मुझे मालूम चला है कि इनके द्वारा शिवपुरी गांव में निजी अस्पताल चलाया जाता है पीड़ित ने बताया की शासन के निर्देशानुसार इनको अधीक्षक पद से हटाकर सीनियर डॉक्टर को अधीक्षक बनाया जाएं साथ ही इनको सीएचसी खखरेरू से स्थांतरण किया जाए जिससे गरीब मरीजों को न्याय व मुफ्त सेवाएं बेहतर मिल सके।

पति से झगड़ा कर खाया जहरीला पदार्थ

फतेहपुर (संवाददाता)। सदर कोतवाली क्षेत्र के अस्ति काषीराम कॉलोनी में पत्नी ने पति से झगड़ा कर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। जिसकी जानकारी उसके परिजनों को हुई तो तुरंत उसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे।

जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के अस्ति काषीराम कॉलोनी निवासी षमीम की 20 वर्शीय पत्नी षमा का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिससे क्षुब्ध होकर उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जिसकी जानकारी उसके परिजनों को हुई तो तुरंत घटना की सूचना सरकारी 108 एम्बुलेन्स को दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एंबुलेंस ने महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तभी वह बिना बताए उठकर कहीं चली गई।

ट्रेन से गिरकर युवक की मौत

फतेहपुर (संवाददाता)। थरियांव थाना क्षेत्र के बहरामपुर रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे ट्रेन से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने षव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। जानकारी के अनुसार असोथर थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव निवासी स्व. अरविंद का लगभग 20 वर्शीय पुत्र करन मुंबई में नौकरी करता था। बताते हैं कि वह ट्रेन से घर आ रहा था। तभी अर्द्धरात्रि बहरामपुर रेलवे ओवर ब्रिज के समीप चलती ट्रेन से गिर गया। सुबह जानकारी होने पर जीआरपी ने मौके पर पहुंच षव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस में घटना के बाबत जानकारी मृतक के चाचा राजू ने दिया।

गम्भीर युवक की कानपुर ले जाते समय मौत

फतेहपुर (संवाददाता)। असोथर थानां क्षेत्र के सांतो धरमपुर गाँव मे ससुराल आये युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहाँ डॉक्टर ने रेफर कर दिया वही देर षाम कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बताते चलें कि खागा कोतवाली क्षेत्र के खेमकरनपुर गांव निवासी केषन पासवान का 30 वर्शीय पुत्र ष्याम पासवान अपनी ससुराल असोथर थाने के सूबेदार का पुरवा मजरे सातों धरमपुर गया था। वहीं पत्नी से विवाद के बाद उसने जहर खा लिया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया था। कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को हुई तो पुलिस ने षव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

खौलती चाय में गिरकर युवक झुलसा, रेफर

फतेहपुर (संवाददाता)। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के नेषनल हाईवे 2 के टोल प्लाजा के समीप होटल में काम करने वाला युवक खौलती चाय पर गिरकर झुलस गया। जिसको इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ केंद्र पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के लक्ष्मनपुर गांव निवासी राम नारायन का 30 वर्शीय पुत्र षिव कुमार विगत 3 वर्शों से थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप स्थित राजस्थान होटल में काम कर रहा है। आज उसको काम करते समय चक्कर आया और वह खौलती चाय के ऊपर गिरकर झुलस गया। तुरंत उसको इलाज के लिए गोपालगंज सीएचसी पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सरकारी 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भर्ती कर उसका इलाज कर रहे हैं।

लोडर की टक्कर से बाइक सवार घायल

फतेहपुर (संवाददाता)। राधा नगर थाना क्षेत्र के सुधवां मोड़ के समीप लोडर की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। घायल अवस्था में उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर भर्ती कर उसका इलाज कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार थरियांव थाना क्षेत्र के टीसी गांव निवासी राम प्रताप सिंह का 23 वर्शीय पुत्र नागेंद्र सिंह बाइक पर सवार होकर किसी काम से राधा नगर थाना क्षेत्र गया था। जब वह सुधवां मोड के समीप पहुंचा, सभी रोड से निकला लोडर उसकी बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गया। जिससे बाइक सवार नागेंद्र सिंह घायल हो गया घटना की सूचना सरकारी 108 एंबुलेंस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एंबुलेंस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भर्ती कर उसका इलाज कर रहे हैं।

बच्ची को बचाने के प्रयास में बाइक सवार गिरकर घायल

फतेहपुर (संवाददाता)। थरियांव थाना क्षेत्र के हसवा कस्बा निवासी युवक किसी काम से कानपुर जनपद गया था। तभी अचानक बाइक के सामने बच्ची आ गई। उसको बचाने के प्रयास में वह गिरकर घायल हो गया। घायल अवस्था में उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के हसवा कस्बा निवासी मो० गफूर का 40 वर्शीय पुत्र मो० अनीस बाइक पर सवार होकर किसी काम से कानपुर जनपद गया था। जब वह चकेरी पहुंचा तभी अचानक उसकी बाइक के सामने बच्ची आ गई। उसको बचाने के प्रयास में वह रोड पर गिरकर घायल हो गया। हादषे की जानकारी उसके परिजनों को हुई तो मौके पर पहुंचे और उसको इलाज के लिए फतेहपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भर्ती कर उसका इलाज कर रहे हैं।

युवक के नाखून उखाड़ने वालों हो गिरफ्तारी -स्वामी प्रसाद

बकेवर। थाना क्षेत्र के पंचमपुर गांव शिवम कोरी को बंधक बनाकर पीटने और पैरों के नाखून उखाड़ने की बर्बरता मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पीड़ित का हाल जानने उसके घर पहुंचे। उन्होंने मुकदमे में धाराएं तरमीम कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।

गांव में आयोजित भंडारे में विवाद के बाद शिवम कोरी को आनंद तिवारी पक्ष ने पीटकर मरणासन्न कर दिया था। मामले में कार्रवाई न होने पर राजनैतिक दल युवक को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और कोरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी गुरुवार को दलित युवक के घर पहुंचे। उन्होंने शिवम कोरी के पिता संतोष कोरी से मुलाकात की। इसके बाद शिवम कोरी का हाल जाना। प्रभारी निरीक्षक कांति सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वार्ता की। दोषियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर केवल सिंह यादव ,राम बरन वर्मा, सुरेंद्र गौतम, राम बहादुर कोरी समेत अन्य मौजूद रहे।

जैविक खेती को बढ़ावा देने को गठित होंगे एफपीओः रवि

फतेहपुर। नमामि गंगे योजना के तहत किसानों को जैविक खेती सिखाने के लिए एक दिवसीय जैविक मेला व प्रदर्शनी का आयोजन भिटौरा ब्लाक परिसर में आयोजित किया गया।कृषि विभाग से नमामि गंगे योजना प्रभारी रवि कुमार ने नमामि गंगे योजना की किसानो को जानकारी दी।उन्होने बताया कि किसान समूह बनाकर जैविक खेती करें।समूहों को मिलाकर जैविक उत्पादों की बिक्री व उत्पादन के लिए किसान उत्पादक कम्पनी का गठन कर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा।रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह ने किसानो को नीम और हरी खाद का जैविक खेती मे महत्व बताया।उन्होनें मेंड़बंदी जरूर करने पर जोर दिया।औषधीय व सगन्ध फसलो का जैविक उत्पादन व वितरण की भी किसानो को जानकारी दी गयी। अश्वगंधा,कालमेघ,भूमि आवला, ब्राह्मी,पमारोशा व खस की खेती के बारे मे औषधीय व सगन्ध खेती विशेषज्ञ ने बताया।रमाकांत तिवारी ने गौ आधारित खेती का महत्व और बीजामृत बनाने की जानकारी दी।मृदा परीक्षण के लिए खेत की मिट्टी के नमूने लेने के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में डॉ प्रेमादान ने बताया।एस एम एस सदर निहाल ने कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान सम्मान निधि,कुसुम योजना,फसल बीमा योजना,फार्म मशीनरी बैंक योजना की सभी जानकारियॉ दी। वही आयोजन की जिम्मेदारी सम्भालते हुए कृषि विभाग की सहयोगी संस्था मनोरमा डबराल जनकल्याण समिति ने किसानों के उत्पादों के स्टाल भी लगवाएं।अध्यक्षता करते हुए सहयोगी सघ्स्था से प्रवीण कुमार,रवि कुमार, आशीष कुमार,गौरव पाण्डेय,शैलेश कुमार पाल धर्मेन्द्र सिंह,व तमाम प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।

उठती है आज मय्यते सुलताने कर्बला होता है दफ्न शाहे शहीदाने कर्बला

कौशाम्बी (संवाददाता)। करारी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एक मोहर्रम से लेकर दस मोहर्रम तक हर रोज़ किसी न किसी के घरों से अलम, ताबूत, जुलजनाह इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की याद में निकाले जाते रहे। दस मोहर्रम बुधवार को इमाम बारगाह से कर्बला गंजे शहीदा ताजिया को ले जाया गया और लविदाई नौहों के साथ दफ्न किया गया।

करारी कस्बा के हज़रत गंज, अंसार गंज, नया गंज, चमन गंज,में दस मोहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अलग अलग इमाम बारगाह में मसायब बयान किए गए। और कदीमी नोहा बयान करते हुए अलग अलग वार्ड के सभी जूलूस कर्बला में एकत्रित हुए जहा अलविदाई नौहा पे जवान बूढ़े बच्चों ने सीना ज़नी व ज़ंजीर जनी की और गंजे शहीदा में ईमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके एकत्तत साथियों की याद में ताजिया को दफ़न किया गया।

मांझियांवा गांव में बड़ी अकीदत मंद से दस मोहर्रम का जुलूस निकाला गया

कौशाम्बी। जुलूस निकालने से पहले दिलदार हुसैन के इमाम बारगाह में इमाम हुसैन अ. के मसायब बयान किया गया। कौसर हुसैन उर्फ गरीब आलम ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इमामबारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एकत्तर की शहादत को पेश किया, शहादत बयां होते ही आजादारों की आंखों से आंसू जारी हो गए मजलिस के फौरन बाद ताजिया अलम, जुलजनाह, बरामद हुए मातम करते हुए धीरे–धीरे जूलूस कर्बला पहुंचा। नौहा बयान करते हुए सोनू, गरीब आलम ,शीमू ,राजू ने पढ़ा उठती है आज मय्यते सुलताने कर्बला होता है दफ्न शाहे शहीदाने कर्बला। गंजे शहीदा में ताजिया को अलविदाई नौहां पढ़ते हुए दफ्न कर दिया गया। इसी तरह लहना, रसूलपुर सोनी ,अंडाहरा, अमुरा सराय सय्यद अली,अगियौना ,मोलानी आदि गांव में इमाम हुसैन की याद में ताजिया उठा कर गंजे शहीदा में दफ्न किया गया।

सेना में जेई पति ने पत्नी को पीटकर घर से निकाला

औंग। सेना में अवर अभियंता (जेई) के पद पर तैनात पति के परिवार वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर युवती को पीटकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति समेत नौ ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव के आनंदपाल सिंह की बेटी प्रिया सिंह उर्फ रितु की शादी 15 फरवरी 2023 को कानपुर बिधनू थाना के कठारा गांव निवासी राहुल सिंह चंदेल से हुई थी। राहुल सेना में जेई हैं और वर्तमान में हरियाणा के हिसार में तैनात हैं। प्रिया का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति व ससुराली दहेज में दो लाख रुपये व इनोवा कार की मांग करने लगे।मांग पूरी न होने पर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देते थे। 23 मई को पति राहुल ने उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया और फिर पीटकर घर से निकाल दिया।

बतकही
हिन्दी साप्ताहिक
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भूपेंद्र सिंह द्वारा दिशेरा प्रेस, श्याम नगर, खम्भापुर, फतेहपुर से मुद्रित तथा ग्राम– रामपुर पचभिटा, मकान नं. 193, पोस्ट– दावतपुर, थाना–मलवां, जिला– फतेहपुर (उ.प्र.) से प्रकाशित।
सम्पादक
भूपेंद्र सिंह